an>

Title: Need to ensure equal educational standards in all the schools and colleges in the country.

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) :** उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में सबके लिए जहां समान कानून व समान शिक्षा का प्रावधान है वहीं शिक्षा का स्तर भी सबके लिए समान होना चाहिए। दुर्भाग्यवश गुलामी के दिनों में ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य में लॉर्ड मैकाले द्वारा ऐसी शिक्षा व्यवस्था का आरम्भ किया गया था जिसका उद्देश्य ही देश में पाश्चात्य संस्कृति के मानने वाले और गुलाम मनोवृति के लोग तैयार करना था। उस शिक्षा व्यवस्था में सम्पन्न लोगों के लिए अलग स्कूल और सामान्य लोगों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था थी जो आज भी चल रही है। देश की आजादी और विकास की एक कसौटी यह भी है कि जब सब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की बात करेंगे। आज की व्यवस्था में गरीब और अमीर का भेद जहां बच्चों में उच्चता व हीनता की भावना पैदा करता है वहां समाज में एकता सूत्र को भेदने का भी काम करता है। हमारी संस्कृति में तो राजा और रंक के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। सही शिक्षा तो समस्याओं के समाधान का दूसरा नाम है, "सा शिक्षा या विमुक्ति"। भगवान के दिये हुए बच्चों में गरीबी और अमीरी का भेद करना न केवल एक पाप है अपितु शासकों व योजनाकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। मेरे क्षेत्र बागपत में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत व सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा के कारण शिक्षा स्तर बहुत गिर गया है। अधिकतर बच्चे जो सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, वे नकल का सहारा लेकर के डिग्री और डिप्लोमा लेते हैं जिससे उन्हें आजकल के प्रतियोगिता युग में कोई रोजगार मिलना भी अत्यन्त कठिन है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में और विशेषकर बागपत लोक सभा क्षेत्र में युवाओं में अपराधीकारण बढ़ रहा है उससे न केवल युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है अपितु कानून का पालन करने वाले लोगों को तथ दिल्ली जैसे राजधानी को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। क्या माननीय शिक्षा मंत्री व भारत सरकार शिक्षा के दोहरे मापदण्ड व व्यवस्था को खत्म करने की कोई योजना तैयार कर रही है।